भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5231

मंगलवार, 24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक भूमि की उच्च कीमतों का प्रभाव

5231. श्री शाहू शहाजी छत्रपती:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नए विनिर्माण निवेशों पर औद्योगिक भूमि की ऊंची कीमतों के प्रभाव की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या देश के कोल्हापुर जैसे टियर-II जिलों में रोजगार सृजित कर रही बड़े निवेश वाली परियोजनाओं के लिए रियायती औद्योगिक भूमि उपलब्ध कराने के लिए कोई नीति अस्तित्व में है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख) "उद्योग" राज्य का विषय है। निवेश संबंधी निर्णय कई कारकों से प्रभावित होते हैं जिसमें, अवसंरचना की उपलब्धता; भूमि की लागत, लॉजिस्टिक्स, वित्त; और ईज ऑफ डूईंग बिजनेस शामिल है। हालांकि, विनिर्माण निवेश पर भूमि लागत के प्रत्यक्ष प्रभाव का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं करवाया गया है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2024 के एक संकल्प द्वारा, 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 6 विनिर्माण क्षेत्रों की अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं की प्रमुख इकाइयों हेतु तथा थ्रस्ट और हाई-टेक क्षेत्र में 4000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करने के लिए नीति की घोषणा की गई है। यह नीति राज्य के किसी भी क्षेत्र में पहली 10 परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन की अनुमति देती है, जिसे बाद में राज्य सरकार के दिनांक 04 अगस्त, 2025 के संकल्प के तहत 10 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। उद्योगों के लिए राज्य सरकार के उक्त संकल्प के अनुसार, थ्रस्ट सेक्टर नीति के तहत, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम और महाराष्ट्र औद्योगिक टाउनशिप लिमिटेड के क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों को कैबिनेट उप समिति के अनुमोदन से प्रचलित भूमि दर में 25 से 50 प्रतिशत तक की रियायत मिलेगी।

*****